प्राक्कथन

केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के बावजूद भी जमीनी वास्तविकता अत्यधिक डांवाडोल है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम पर अत्यधिक निधियों का व्यय हो चुका है। धारणागत ढांचे को भी सतत रूप से परिवर्तित किया गया था। तथापि, मुख्य मुद्दा खुले में शौच की समाप्ति ही है, एक ऐसा आचरण जो न केवल हमारे राष्ट्र के प्रतिबिम्ब पर एक दाग है, जन स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि मानव गरिमा के भी प्रतिकूल है।

यह अखिल भारतीय लेखापरीक्षा ग्रामीण स्वच्छता के प्रबन्ध का मूल्यांकन करता है तथा उन कारणों का विश्लेषण करता है कि सरकार क्यों इस संगीन सामाजिक-आर्थिक सूचक, जो हमारे पड़ोसियों की तुलना में भी भारत के वैश्विक श्रेणी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, पर विफल है। यह कार्यक्रम, जो करीब तीन दशकों से मिशन मोड में चल रहा है, विभिन्न सरकारी अभिकरणों, भागीदार गै.स.सं तथा कार्पोरेट में अपेक्षित मिशनरी उत्साह का आहवान करने में भी सफल नहीं हुआ है। कार्यक्रम के सफल होने के लिए आवश्यक समायोजित दृष्टिकोण जैसे संसाधनों-धन, जन तथा वस्तु का उपयोग, लक्षित जनसंख्या के बीच जागरूकता पैदा करना, निगरानी तंत्र तथा प्रभावी प्र.सू.प्र. के उपयोग, प्राय: अविद्यमान है। यदि कार्यक्रम को सफल बनाना है तो इनके क्रियान्वयन में इन कमियों को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हम आशा करते हैं कि भारत के सविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई यह रिपोर्ट अति राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सम्मिलित नियोजकों तथा प्रशासकों को कुछ संकेतो का उल्लेख करेगा।